केन्द्रीय बजट 2018-19 में शिक्षा

नेसार अहमद

पिछले कई वर्षों में बजट में शिक्षा की प्राथमिकता लगातार कम हो रही है। वर्ष 2018-19 के बजट में भी मानव संसाधन मंत्रालय का बजट पिछले वर्ष की अपेक्षा 7 प्रतिशत बढ़ा है, लेकिन कुल बजट के प्रतिशत के रूप में शिक्षा पर आवंटन पिछले वर्ष के 3.8 प्रतिशत (2017-18 संशोधित अनुमान) के मुकाबले इस वर्ष 3.6 प्रतिशत रह गया है। भारत सरकार की प्राथमिकताओं में शिक्षा की उपेक्षा को देश के सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में शिक्षा बजट के लगातार कम होते जाने से भी समझा जा सकता है (चार्ट 1)।

मानव संसाधन मंत्रालय का कुल बजट (प्रतिशत)

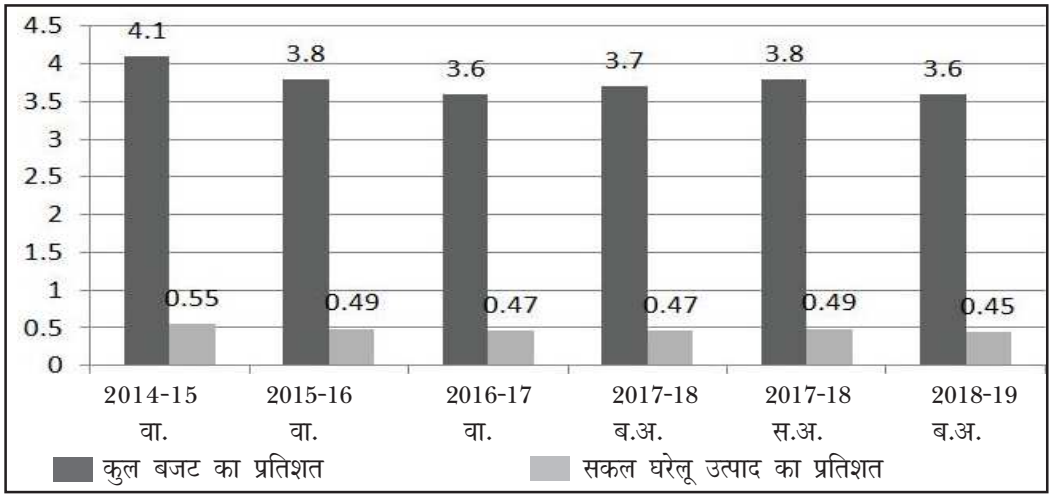

नोट : वा. - वास्तविक, **ब.अ.** - बजट अनुमान, **स. अ.** - संशोधित अनुमान

नीति आयोग ने अपने तीन वर्ष के एक्शन एजेंडा (2017-18 से 2019-20) में सीखने के नतीजों (लर्निंग आउटकम) पर काफी जोर दिया है। वर्तमान बजट भाषण में भी इसको फिर से रेखांकित किया गया है। लेकिन सरकार के आंकड़ों के अनुसार ही देश के प्राथमिक स्तर के 66.41 लाख शिक्षकों में से 11 लाख शिक्षक अभी भी अप्रशिक्षित हैं (इनमें से 5.12 लाख सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में हैं और बाकी निजी विद्यालयों में हैं)। सभी शिक्षक शिक्षा का अधिकार कानून के मानकों को पूरा करें इस कोशिश में सरकार के एक बार फिर शिक्षा का अधिकार कानून को संशोधित कर कानून में दिए गए शिक्षकों के न्यूनतम योग्यता को पूरा करने की अवधि को 2019 तक बढ़ा दिया है। अभी तक अप्रशिक्षित शिक्षकों के मुद्दे को मुख्यतः सर्व शिक्षा अभियान और माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों के प्रशिक्षण के द्वारा ही हल करने पर जोर दिया गया है। लेकिन सबसे महत्तवपूर्ण है शिक्षक प्रशिक्षण के लिए संस्थागत

क्षमता बढ़ाना। इस बजट में शिक्षक प्रशिक्षण के लिए संस्थागत क्षमता के लिए 550 करोड़ रुपये रखे गए हैं, जो पिछले बजट से 70 करोड़ अधिक है।

विभिन्न योजनाओं का बजट

अगर प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग की मुख्य योजनाओं की बात करें तो सर्व शिक्षा अभियान का बजट पिछले वर्ष के अपेक्षा 2629 करोड़ रुपये बढ़ा है जो पिछले वर्ष से 11 प्रतिशत अधिक है। वहीं माध्यमिक शिक्षा अभियान के बजट में 7 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है जबकि शिक्षक प्रशिक्षण एवं प्रौढ़ शिक्षा का बजट मात्र 4 प्रतिशत से भी कम बढ़ा है। (सारणी 1)

सारणी 1 मुख्य योजनाओं का बजट (रुपये करोड़)

राष्ट्रीय शिक्षा मिशन	2014–15 वा.	2015–16 वा.	2016–17 वा.	2017–18 ब.अ.	2017–18 स.अ.	2018–19 ब.अ.
सर्व शिक्षा अभियान	24097	21661	21685	23500	23500	26129
माध्यमिक शिक्षा अभियान	3398	3563	3698	3830	3915	4213
शिक्षक प्रशिक्षण एवं प्रौढ शिक्षा	1158	916	817	926	841	871

नोट : वा. - वास्तविक, **ब.अ.** - बजट अनुमान, **स.अ.** - संशोधित अनुमान

अन्य योजनाओं में, अगर स्कूलों में मध्याह्न भोजन के बजट को देखें तो, इस महत्त्वपूर्ण योजना का बजट 10,000 करोड़ रुपये (2017-18 स.अ.) से बढ़ा कर 10,500 करोड़ रुपये (2018-19 ब.अ.) कर दिया गया है।

उच्च शिक्षा में तकनिकी शिक्षा और शिक्षा के लिए कर्ज को बढाने पर जोर

2018-19 (ब.अ.) में 35,010 करोड़ रुपये उच्च शिक्षा विभाग को आवंटित हुए हैं जो 2017-18 से बस 5 प्रतिशत अधिक है। बजट में एक घोषणा 2022 तक कुल एक लाख करोड़ के निवेश से ''शिक्षा में बुनियादी संरचना और व्यवस्था सुधार'' को लागू करने की भी की गई है, जिसके द्वारा प्रमुख शिक्षण संस्थाओं में शोध और संबंधित अधोसंरचना को बढ़ावा दिया जाएगा।

हमेशा ही उच्च शिक्षा के बजट में तकनिकी शिक्षा को अधिक प्राथमिकता मिलती रही है। पिछले कुछ वर्षों में शिक्षा के लिए कर्ज की मांग भी बढ़ी है, और इसे केंद्रीय बजट में भी ध्यान में रखा गया है। जहां राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान का बजट 100 करोड़ रुपये बढ़ाया गया है, वहीं शिक्षा के कर्ज के लिए ब्याज सब्सिडी और गारंटी फण्ड में 1950 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई है। साथ ही उच्च शिक्षा वित्त संस्था के बजट को 250 करोड़ रुपये से बढ़ा कर 2750 करोड़ रुपये कर दिया गया है। जाहिर है सारा जोर उच्च शिक्षा के निजीकरण और छात्रों के लिए कर्ज की उपलब्धता पर है!

बालिका शिक्षा

ऐसा कहा गया कि सरकार ने आर्थिक समीक्षा 2018 का रंग गुलाबी रख कर यह संदेश दिया है कि सरकार महिला सशक्तिकरण के पक्ष में है। लेकिन शिक्षा के बजट में ऐसा कुछ ठोस नहीं दिखा जो महिल शिक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ाता हो। बलिकाओं के माध्यमिक शिक्षा के प्रोत्साहन के लिए राष्ट्रीय योजना का बजट 320 करोड़ रुपये (2017-18 ब.अ.) से घटा कर 256 करोड़ रुपये (2018-19 ब.अ.) कर दिया गया और तमाम प्रचार के बावजूद 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' योजना के 100 करोड़ रुपये में से 2016-17 में केवल 29 करोड़ रुपये ही खर्च हो पाए। यह सभी आंकड़े इस ओर इशारा करते हैं कि सरकार की प्राथमिकताओं में शिक्षा पिछड़ती जा रही है। ◆

लेखक परिचय : जयपुर स्थित बजट अध्ययन राजस्थान केन्द्र (बार्क) के समन्वयक हैं।
संपर्क : ahmadnesar@gmail.com